कच्चा थीबू का दावा

322. श्री राम जेठमलानी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कच्चा थीबू द्वीप के संबंध में तमिलनाडु विधान सभा द्वारा हाल ही में पारित एक संकल्प की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा यह मांग की गयी है कि कच्चा थीबू को पुन: भारत में मिला दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सबध में ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) तमिलनाडु विधान सभा ने 3 अक्तूबर, 1991 को जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें दूसरी बातों के अलावा, भारत सरकार से यह अपील की गई थी कि वह "कच्चा थीबू तथा इसके आसपास के समुद्र को वापस दिलाने तथा उन्हें भारतीय प्रदेश में पुन: शामिल करने" के लिए श्रीलंका सरकार के साथ तत्काल कार्रवाई करे। भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा जिसे 1974 और 1976 के समुद्र सीमा करारों के माध्यम से अंकित किया गया था, के संबंध में सरकार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन करारों के अनुसार कच्चा थीबू द्वीप अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के श्रीलंका की ओर पड़ता है।

बंगलादेश में उल्फा उग्रवादियों को प्रशिक्षण

@323. श्री राम जेठमलानी :
श्री रणजीत सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के उल्फा-उग्रवादियों को, जो कि विध्वंसकारी गतिविधियों में अन्तर्लिप्त हैं, बंगलादेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश में कितने उग्रवादी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को बंगलादेश सरकार के समक्ष उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, और प्रशिक्षित उग्रवादियों की भारत में घुसपैठ को रोकने और सीमा को बन्द करने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) (क) और (ख) सरकार को ऐसी खबरों की जानकारी है जिनसे यह पता चलता है कि कुछ "उल्फा" उग्रवादियों को सीमा पार बंगलादेश से प्रशिक्षण और अन्य सहायता मिल रही है।

(ग) जी, हां ।

(घ) बंगलादेश की सरकार ने इस बात का जोरदार खंडन किया है कि उल्फा को किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है अथवा बंगलादेश में "उल्फा" के ठिकाने हैं । बंगलादेश से 3 उग्रवादियों और अन्यों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा कड़ी चौकसी बरती जाती है ।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्यक्रम में सुधार

324. श्री रणजीत सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को लगातार घाटा हो रहा है ;

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न संख्या 104, 9-11-1991 से स्थानान्तरित ।

(ख) यदि हां, तो इस निगम को क्रमशः वर्ष 1989-90, 1990-91, और 1991-92 की प्रथम छमाही के दौरान कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस निगम द्वारा चलायी जा रही लगभग 4,000 बसों के लिए इसमें लगभग 4,3000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) अक्टूबर, 1991 के दौरान इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या थी, और प्रशासनिक खर्चों को कम से कम करने और इसकी कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (सितम्बर, 91 तक) के दौरान हुआ कुल घाटा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(लाख रु.)
1989-90	11984.56
1990-91 (अनन्तिम)	19748.35
अप्रैल से सितम्बर, 1991 (अनन्तिम)	10915.32

(ग) और (घ) 31-10-91 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 41,161 थी। प्रशासनिक खर्चों को न्यूनतम स्तर पर लाने के विचार से दिल्ली परिवहन निगम ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने और मृतक कर्मचारियों के निकट संबंधियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के सिवाय और सभी भर्तियां बंद करने का निर्णय किया है।

सरकार, दिल्ली परिवहन निगम की उत्पादकता को बढ़ाने और प्रचालन की लागत कम करने, अधिक-उपाय लागू करने तथा अधिक राजस्व अर्जित करने और कार्यचालन घाटों को कम करने की दृष्टि से चोरी को रोकने के लिए इसके कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखे हुए हैं। दिल्ली परिवहन निगम अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए रूटों का भी युक्तिसंगत बना रहा है।

Pendng projects of Rajasthan

325. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the number of projects/schemes pertaining to Rajasthan which are pending clearance with his Ministry at present and the progress made so far in each case; and

(b) what is the time that is likely to be taken by the Central Government in each case for approval and what are the reasons for delay if the case is pending for more than six months?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) References about various road and bridge schemes from Rajasthan pending with the Government are mentioned below alongwith their position:

(i) 4 schemes for conversion of State Roads into National Highways and 13 schemes to be taken up under the Economic and Inter-State Importance Programme. These proposals can be considered only after the finalisation of the 8th Plan.

(ii) 33 schemes proposed to be financed against the augmented Central Road Fund. These would be processed after actual augmentation of the Central Road Fund, which has not yet taken place.